भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3043
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस)

†3043. श्री बापी हलदरः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रमुख और गौण खनिजों के संदिग्ध अवैध खनन के संबंध में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी चेतावनियां जारी की गई हैं;
(ख) कितने मामलों में कार्रवाई की गई है;
(ग) कितने मामले हैं जिनमें अवैध खनन का पता चला है; और
(घ) अवैध खनन के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और जारी की गई चेतावनी पर कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) से (घ): खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) द्वारा जारी किए गए ट्रिगर्स की उनके सत्यापन के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और पता लगाए गए अवैध खनन के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

(दिनांक 30.01.2026 **तक)**

राज्य	**उत्पन्न ट्रिगर्स**	**सत्यापित किए गए ट्रिगर्स**	**पुष्टि किए गए अवैध खनन के मामले**
असम	2	0	0
आंध्र प्रदेश	100	83	9
बिहार	2	0	0
छत्तीसगढ़	84	11	1

गोवा	74	72	29
गुजरात	148	102	23
हरियाणा	4	2	0
हिमाचल प्रदेश	21	11	0
जम्मू और कश्मीर	26	22	1
झारखंड	48	5	0
कर्नाटक	79	79	3
केरल	5	3	3
मध्य प्रदेश	143	105	9
महाराष्ट्र	38	15	3
मेघालय	56	1	0
ओडिशा	42	26	0
राजस्थान	105	73	3
तमिलनाडु	87	46	12
तेलंगाना	14	13	0
उत्तर प्रदेश	10	0	0
कुल	1088	669	96

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों (प्रमुख और गौण दोनों) के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और उनसे जुड़े प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, खनिजों के निष्कर्षण और ढुलाई सहित अवैध खनन की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

*****